Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

36 वां सप्रू हाउस व्याख्यान

महामहिम ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन

आर्कटिक सर्कल के अध्यक्ष

द्वारा

सप्रू हाउस, नई दिल्ली
4 मार्च 2020

आर्कटिक और तृतीय ध्रुव
भारत में कीनोट संबोधन

महामहिम ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन द्वारा 36 वां सप्रू हाउस व्याख्यान

आर्कटिक सर्कल के अध्यक्ष

आइसलैंड का राष्ट्रपति 1996-2016

व्याख्यान लिखित नोट्स के बिना दिया गया था

महामहिम, देवियों और सज्जनों। सबसे पहले मैं मुझे आमंत्रित करने के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद और आर्कटिक सर्कल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डेगफिनूर स्वेनहॉर्सन को इस मंच पर उपस्थित होने और आज यहाँ पर सप्रू हाउस व्याख्यान देने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा।

मैं बहुत समय पहले पहली बार भारत आया था। मुझे 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने और उनके उत्तराधिकारी राजीव गांधी के साथ-साथ पांच अन्य नेताओं, जिनमें ओलोफ पाल्मे, एंड्रियास पापांड्रेउ और जूलियस न्येरे शामिल थे, के साथ सहयोग करने का अवसर मिला। इसे छह राष्ट्रों की शांति पहल (सिक्स नेशन पीस इनिशिएटिव) कहा गया; शीत युद्ध के चरम पर जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव था, पूर्वी और पश्चिमी खंडों ने दुनिया के हर महाद्वीप पर कब्जा कर लिया था। मेरे लिए यह भारत के साथ एक लंबे समय के मित्रता की शुरुआत थी, सीखने का एक अनुभव था जिसने मुझे कई तरीकों से लाभान्वित किया है, मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है, मेरे ज्ञान और लोकतंत्र, संस्कृति, आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण को समृद्ध किया है और यह भी समझाया कि कैसे एशिया का उदय 21 वीं सदी में दुनिया पर हावी होगा। इसलिए, मैं भारत का हार्दिक आभारी हूँ; मेरे अपने देश के अलावा ऐसे बहुत कम देश हैं, जिन्होंने मुझे इतने लंबे समय में इतना कुछ दिया है।

जैसा कि मैंने आपके प्रधान मंत्री को लिखे हालिया पत्र में कहा था, मुझे कई दशकों में उनके पांच पूर्ववर्तियों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। कल और परसों, मैं प्रधान मंत्री की ओर से आपके विदेश मंत्री, आपके जलवायु मंत्री और आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से मिला और हमारे मध्य आर्कटिक में भारत की संलिप्तता को बढ़ाने पर चर्चा हुई और इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे आर्कटिक सहयोग मॉडल का सबक हिमालयी देशों की बढ़ती आवश्यकताओं को लाभान्वित कर सकता है कि वे एक आम मंच पर एक-साथ आएं और जांच कर सकें कि आपके तात्कालिक पड़ोस में हिमनदियों का क्या हो रहा है।

कई लोगों को आश्चर्य होगा है कि भारत को इस दूरस्थ स्थान, आर्कटिक में दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए। भारत सरकार, व्यवसाय समुदाय, पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता क्यों होनी चाहिए कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड के बर्फ से ढके पड़ोस और रूस, अलास्का के जमे हुए टुन्ड्रा और दुनिया के इस छोर के आस-पास के अन्य भागों में क्या हो रहा है। उत्तर वास्तव में बहुत स्पष्ट है कि भारत का भविष्य काफी हद तक आर्कटिक द्वारा निर्धारित होगा और आर्कटिक का भविष्य भी इससे निर्धारित होगा कि भारत और अन्य एशियाई देशों में क्या होता है। इस नई सदी में हम सब का भाग्य परस्पर रूप से इतना जुड़ा हुआ है, कि दुनिया के सभी हिस्सों की गहरी समझ और जुड़ाव के बिना, एक या दूसरे विषय पर चर्चा करना असंभव है।

बेशक, आर्कटिक कुछ हद तक एक मिथ्या नाम है, क्योंकि हम अक्सर इसके बारे में इस तरह बात करते हैं, मानो कि यह लैपलैंड या स्कॉटलैंड या ऐसे ही अन्य छोटे भौगोलिक क्षेत्र हों। हम वास्तव में दुनिया के एक बड़े हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, जो किसी महाद्वीप के अनुपात का है। अलास्का अकेले टेक्सास के आकार का तीन गुना है, ग्रीनलैंड पश्चिमी यूरोप के आधे हिस्से के बराबर है और रूसी आर्कटिक सात समय क्षेत्रों को कवर करता है जो महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार के दोगुने से अधिक है। हम आर्कटिक के बारे में अपने परंपरागत तरीके से जिस तरह बात करते हैं, उसे देखते हुए, अब 21 वीं सदी की शुरुआत में यह समझना बहुत मुश्किल है कि यदि हम इन सभी क्षेत्रों को एक-साथ जोड़ दें तो यह वास्तव में ग्रह का एक विशाल हिस्सा है। और बेशक, दुनिया के प्रबुद्ध शिक्षित जगत, चाहे वे एशिया, यूरोप या संयुक्त राज्य के या कहीं और के शिक्षित व्यक्ति हों, सदियों तक इस बात से पूरी तरह अनजान थे। बेशक, वहां के स्वदेशी लोग कई सदियों से, यहाँ तक कि कई सहस्राब्दियों से वहां रहते आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो पिछली शताब्दियों में भारतीयों के वंशज रहे होंगे। इसीलिए, जब पहले नॉर्वेजियन, अंग्रेजी, कनाडाई खोजकर्ता 20 वीं सदी की शुरुआत में आर्कटिक में पहुंचे, तो वे विश्व प्रसिद्ध हो गए क्योंकि वे वास्तव में इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले लोग थे और फिर उन्होंने प्रबुद्ध जगत को बताया कि यह जगह कैसी है। हालांकि तीन या चार साल तक कोई नहीं जानता था कि वे जीवित हैं या नहीं, पर उसके बाद वे जीवित वापस लौट आएं। और फिर पश्चिमी और पूर्वी खंडों के बीच गहन सैन्यीकरण और संघर्ष और सामरिक शत्रुता के कारण शीत युद्ध ने ग्रह के इस हिस्से को बंद करवा दिया।

तो विरोधाभासी रूप से मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रह का यह विशाल हिस्सा केवल पिछले 20 वर्षों में ही राजनयिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए खुला है। इस ग्रह का ऐसा कोई अन्य हिस्सा नहीं है जहाँ अनेकों राज्य और समुदाय और लोग और संस्कृतियां बसी हुई हैं जो बहुत हाल ही में व्यापक बहुआयामीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए खुला है। इस बदलाव की गति इतनी तेज रही है, विशेष रूप से, पिछले पांच या दस वर्षों में, कि हो रही घटनाओं को समझना और उनसे निष्कर्ष निकालना हम में से सबसे प्रबुद्ध लोगों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। मात्र सात साल पहले ही आर्कटिक परिषद, एक ऐसी अंतर-शासकीय संस्था जिसका गठन संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और नॉर्डिक देशों के हम पांच देशों द्वारा केवल 20 साल पहले ही हुआ है, ने भारत, चीन, कोरिया, जापान और सिंगापुर को आर्कटिक परिषद में एक प्रेक्षक राज्य के रूप में स्वीकार किया है।

यदि किसी ने भी किरुना की बैठक, जिसमें जॉन केरी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि थे, में यह कहा होता, कार्ल बिल्ड्ट स्वीडन की ओर से अध्यक्ष थे। लेकिन दशक समाप्त होने से पहले चीन, कोरिया, जापान आर्कटिक सहयोग में अत्यंत सक्रिय भागीदार बन जाएंगी कि अब हम पिछले तीन वर्षों से देख रहे हैं कि ये तीन एशियाई देशों जापान, कोरिया और चीन ने अपने आर्कटिक नीति के समन्वय के लिए अपने विदेश मंत्रालयों के स्तर पर अपने मध्य नियमित त्रिपक्षीय परामर्श बैठक संचालित किया है। आर्थिक सहयोग और निवेश, वैज्ञानिक अनुसंधान, और राजनयिक सहयोग के क्षेत्र में उनका जुड़ाव अब इतनी वृहद हो चुकी हैं कि मैंने उन्हें प्रेक्षक राज्य (आब्जर्वर स्टेट्स) कहना बंद कर दिया है, अब मैं उन्हें आर्कटिक का कार्य राज्य (एक्शन स्टेट्स) कहता हूं।

लेकिन, मेरे प्यारे दोस्तों, इस देश का एक अच्छा दोस्त होने के नाते, मैं कहना चाहूँगा कि आर्कटिक प्रेक्षक राज्यों के इस एशियाई परिवार में भारत अब भी किसी तरह रेलवे स्टेशन पर ही अटका हुआ है, पर हम में से कई लोगों ने सोचा था कि यह पांच या दस साल पहले ही आर्कटिक स्टेशन बन जाएगा, जबकि बाकी अन्य एशियाई देशों के साथ-साथ यूरोपीय देशों जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों ने अपना दबदबा बढ़ाया है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आर्कटिक की पिछली सुख्यात भौगोलिक चित्र की तुलना में सभी सदस्य राज्यों और प्रेक्षक राज्यों का मानचित्र शायद आर्कटिक खेल मैदान, जो हम अभी देख रहे हैं, के बारे में अधिक जानकारी देता है क्योंकि इसमें केवल आर्कटिक के आठ क्षेत्रीय राज्य ही नहीं हैं बल्कि प्रेक्षक राज्य भी हैं, जिन्हें आर्कटिक टेबल पर एक निश्चित भूमिका के लिए औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है और जिसमें एशियाई राज्य और केवल फ्रांस और जर्मनी ही शामिल नहीं हैं बल्कि इटली, स्विट्ज़रलैंड और विश्व के अन्य देश भी शामिल हैं। और आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कि अग्रणी प्रमुख देशों का यह समूह, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, कोरिया, जापान, कनाडा फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटन आदि शामिल हैं, किसी न किसी

तरह से आर्कटिक के खिलाड़ी हैं। बेशक, इसके कई कारण हैं, या हमने कुछ कारणों को सूचीबद्ध किया है। बेशक, आर्कटिक ऊर्जा स्रोतों से भरपूर है। ये एक कारण है। रूस के निर्यात की 20% से अधिक आमदनी अब रूसी आर्कटिक से आती है। इसके अलावा यह घटित होने वाली भूराजनीतिक रूपांतरण का प्रतिबिम्ब है कि रूस की सरकार हाल ही में पुनर्गठित हुई है और इसमें न केवल आर्कटिक के लिए मंत्रालय बनाया गया है बल्कि सुदूर पूर्व और आर्कटिक के लिए भी संयुक्त रूप से एक मंत्रालय बनाया गया है। रूस से यूरोप तक गैस की पाइपलाइनें बिछीं हैं लेकिन हाल ही में रूसी आर्कटिक से लेकर चीन के शंघाई तक 8,500 किमी की पाइपलाइन बिछाई गई है।

तेल और प्राकृतिक गैस के अलावा, आर्कटिक अन्य स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य में भी बहुत समृद्ध है, यही एक कारण है कि मेरा अपना देश-आइसलैंड और ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी शक्तियां हैं।

आर्कटिक में न केवल रूस बल्कि ग्रीनलैंड, कनाडा और अन्य भाग भी असाधारण रूप से खनिजों से समृद्ध हैं। विशेष रूप से 21 वीं सदी में उच्च प्रौद्योगिकी वाले आईटी उद्योग के लिए अनिवार्य दुर्लभ धातुओं, तत्वों का खनन लगातार महत्व प्राप्त करता रहेगा। 21 वीं सदी में भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य देशों के लिए आर्कटिक के दुर्लभ धातुओं और खनिजों तक पहुंच प्राप्त कर आईटी क्षेत्र में किसी एक या अन्य तरीके से वैश्विक अग्रणी बना रहना असंभव है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को खरीदने के बारे में ट्वीट इसलिए किया था क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को एहसास हो गया है कि ग्रीनलैंड में इतने समृद्ध संसाधन हैं कि न केवल सामरिक कारणों से बल्कि 21 वीं सदी में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी, यह एक आदर्श भागीदार होगा। इसलिए जिन लोगों ने सोचा कि राष्ट्रपति अपने ट्वीट के ज़रिए बस मज़ाक कर रहे थे, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए ग्रीनलैंड के सामरिक आर्थिक महत्व के समझ को प्रतिबिंबित करता है।

आर्कटिक असाधारण रूप से महासागरीय संसाधनों से समृद्ध है। यह वास्तव में एक ऐसा प्रमुख अप्रदूषित क्षेत्र है जहां मछली पकड़ने वाले जहाजी बेड़े अब भी मछली पकड़ सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राज्य सचिव जॉर्ज शुल्ट्ज़, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महान वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, ने कुछ सालों पहले कहा था: कल्पना कीजिए कि आपको कल सुबह की न्यू यॉर्क टाइम्स मिली है और उसकी मुख्य सुर्ख़ियों में लिखा है कि ग्रह पर एक नया महासागर है। ऐसा कह कर वे हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहते थे कि आर्कटिक महासागर के बर्फ का पिघलना मानव इतिहास में पहली बार ग्रह पर एक नया महासागर सृजन कर रहा है। एक ऐसा महासागर, जो, सुएज़ कैनाल या होरमुज़ की खाड़ी के ज़रिए नहीं, उन क्षेत्रों के ज़रिए नहीं जिसने सिंगापुर को एक मुख्य केंद्र बनाया है, बल्कि उत्तरी समुद्री मार्ग के ज़रिए नई सी-लाइनों और शिपिंग का एक क्षेत्र बन सकता है। रूसी तट के उत्तर पूर्वी समुद्री मार्ग - संयोग से शिपिंग व्यवस्था के लिए रूस में पहले से ही एक विधायी रूपरेखा मौजूद है - या सेंटर रूट नामक मार्ग के माध्यम से ध्रुव के पार, जिसमें चीन विशेष रूप से रूचि रखता है। चीन की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी कॉस्को (COSCO) ने पांच से अधिक वर्षों से एक व्यवस्थित आर्कटिक शिपिंग रणनीति पर काम किया है, और कोरिया पहले ही उन्नत टैंकरों के निर्माण में लगा हुआ है जो उत्तरी समुद्री मार्ग से जलयात्रा करते हुए एलएनजी परिवहन कर सकेगा और इसके लिए आइसब्रेकर्स को साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आर्कटिक महासागर के खुलने के कारण, हमें लगातर ये देखने को मिल रहा है कि दुनिया की प्रमुख शिपिंग कंपनियां एशिया से यूरोप और अमेरिका तक माल पहुँचाने की इस नई संभावना पर ध्यान दे रही हैं। इसमें पुराने सुएज़ कैनाल के रास्ते सफ़र से 10 दिन कम लगता है। आपको केवल सुएज़ कैनाल की जंग और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इसके सामरिक महत्व को याद करना है। बेशक, भारत को हमारे ग्रह पर नए समुद्री मार्ग खुलने के परिणामों को समझने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कोई सबक लेने की आवश्यकता नहीं है।

आर्कटिक के खुलने का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम ऊर्जा क्षेत्र है। कुछ महीने पहले, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के साइबेरिया के कठिन चुनौतीपूर्ण आर्कटिक क्षेत्र से नीचे दूर शंघाई तक जाने वाले 8,500 किलोमीटर लम्बे विशाल पाइपलाइन के उद्घाटन का संयुक्त रूप से जश्न मनाया। जैसा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, यह इन दो राष्ट्रों की

इंजीनियरिंग और निर्माण कौशल का साक्ष्य है क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से रूसी आर्कटिक के कठिन क्षेत्रों और मौसमी स्थितियों में इस पाइपलाइन का निर्माण किया है। और इस परियोजना के पैमाने को समझाने के लिए मैंने हाल ही में अपने अमेरिकी दोस्तों से कहा कि वे अमेरिका के मानचित्र पर 8,500 किलोमीटर लम्बे पाइपलाइन को दर्शाते हुए एक रेखा खींचे। और जब दक्षिणी चीन अपनी ऊर्जा के लिए रूसी आर्कटिक पर निर्भर हो गया है, जब शंघाई ने जमे हुए रूसी टुन्ड्रा के ऊर्जा तक पहुँचने के बारे में अपने भविष्य की योजना बना ली है, तो हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि ऐसा कुछ तो जरूर हुआ है जिसने 21 वीं सदी में ऊर्जा की भूराजनीति को देखने का नज़रिया बुनियादी तौर पर बदल दिया है।

साइबेरिया की ऊर्जा शक्ति शायद इसके लिए हमारी मार्गदर्शक अवधारणा है। यही कारण है कि क्यों रूसी सरकार ने रूसी आर्कटिक को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाया है और क्यों राष्ट्रपति पुतिन हर दूसरे वर्ष सेंट पीटर्सबर्ग में बड़े सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं, जिसमें सभी प्रमुख रूसी मंत्री भाग लेते हैं और बड़ी रूसी कंपनियां भी, क्योंकि आर्कटिक की ऊर्जा के उपयोग के बिना हम रूस के ऊर्जा भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा केवल चीन के संबंध में नहीं है, बल्कि भारत सहित अन्य पड़ोसी देशों के संबंध में भी है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधान मंत्री मोदी के समक्ष रूसी आर्कटिक से लेकर भारत तक ऐसा ही एक पाइपलाइन बनाने की संभावना का प्रस्ताव रखा था। यूरोप में भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 और ऐसे अन्य पाइपलाइन जाते हैं। एक साल पहले आयोजित म्युनिक सुरक्षा सम्मेलन में, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख सीनेटरों और अन्य लोगों ने जर्मनों और यूरोपीयों को यह समझाने की कोशिश की कि उन्हें रूस के साथ ऊर्जा व्यापार जारी नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो स्पष्ट है कि शंघाई और चीन की तरह महाद्वीपीय यूरोप ने भी रूस से आने वाली धारा पर अपनी ऊर्जा भविष्य की परिकल्पना की है जो 21 वीं सदी में जारी रहेगी। और भारत के लिए एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, मेरा मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन ने 21 वीं सदी के भविष्य में नए ऊर्जा प्रणाली के निर्माण में भारत को चीन, यूरोप और रूस के साथ इस त्रिकोण में प्रवेश करने के बारे में पूछ कर दोहराया है। एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच शिपिंग के अलावा, हमारे पास एक नया ऊर्जा निर्माण है। हमें केवल 21 वीं सदी में तेल के महत्व को समझना है ताकि हम इन नई ऊर्जा संरचनाओं के भू-राजनीतिक परिणामों को समझना शुरू कर सकें, जिसके बारे में मैंने अभी-अभी बताया है। मेरा अनुमान है कि कभी न कभी पीएम मोदी की सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और व्यवस्थित रूप से खोज शुरू होगी कि भारत को इस नए निर्माण के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। और फिर, बेशक, भारत के लिए आर्कटिक के परिणाम हर किसी को स्पष्ट नज़र आएँगे।

जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, यह केवल शिपिंग और ऊर्जा और खनिजों और दुर्लभ धातुओं या महासागरीय संसाधनों के बारे में नहीं है, यह मौसमी स्वरूपों और जलवायु के बारे में भी है। यह मानसून के बारे में भी है। और आर्कटिक के बर्फ के साथ जो कुछ भी और जैसे हो रहा है, उसका मौसमी स्वरूपों और चीन, भारत और एशिया के अन्य देशों और साथ ही विश्व के हर महाद्वीप के समुद्र स्तरों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ग्रीनलैंड के बर्फ की चादर का पिघलना ऐसा ही है और इसके परिणाम दुनिया के हर देश के लिए इतने भयानक हैं कि यदि ग्रीनलैंड में मौजूद बर्फ का केवल एक-चौथाई हिस्सा भी पिघलता है, और यह बहुत तेजी से पिघल भी रहा है, तो दुनिया भर में समुद्र स्तर दो मीटर बढ़ जाएगा। भारत के तटीय शहरों को ही देखिए और सोचिए कि यदि समुद्र स्तर दो मीटर बढ़ जाए तो मुंबई या भारत के अन्य तटीय शहरों का क्या हाल होगा। चीन के दक्षिणी शहरों और ग्रीनलैंड के बर्फ की चादर के पिघलने के बीच इस संबंध को चीन पहले ही पहचान चुका है।

आर्कटिक में समुद्री बर्फ का आक्रामक ढंग से पिघलना, एशिया के मौसमी स्वरूपों पर भारी प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से हाल के वर्षों में भयंकर विनाश हुआ है। तो, आर्कटिक के बर्फ का और मेरे देश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दिए बिना, हम वास्तव में अपने देश और पड़ोसी एशियाई देशों या दुनिया के अन्य हिस्सों के मौसमी स्वरूप को नहीं समझ सकते, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भयंकर शर्दी पड़ना जिसने पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में भारी नुकसान और कठिनाइयां पैदा की हैं।

ध्रुवीय भंवर और अमेरिका और एशिया की जलवायु के मौसमी स्वरूपों को समझने के लिए इसके परिवर्तनों का निहितार्थ, बेशक, अब अभिस्वीकृत वैज्ञानिक ज्ञान का बुनियादी हिस्सा है। शायद 20 साल पहले इसे नहीं पहचाना गया था और हमें याद रखना चाहिए कि मात्र 1970 के दशक में ही वैज्ञानिकों ने दुनिया भर की समुद्री धाराओं के कन्वेयर बेल्टों की पहचान की था। तो, वास्तव में हमने या वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय ने हाल ही में ध्रुवीय भंवर और दुनिया के सभी बड़े महाद्वीपों के जलवायु पर इसके मौसमी स्वरूपों के अंतर-संबंधों के बारे में समझा है कि इसमें क्या होता है। इसलिए यह समझा जा सकता है कि दूसरों को या सामान्यतः आम लोगों को इस अंतर-संबंध के बारे में समझने में समय लगता है।

इस संदर्भ में, आर्कटिक की प्रासंगिकता इस संबंध में भी महत्वपूर्ण है कि आपके बर्फ से ढके पड़ोस में क्या हो रहा है। ग्रह पर केवल ऐसे तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जो बर्फ से ढके हैं। अंटार्कटिका, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि यहाँ कोई राज्य या जनता नहीं है। हमें ये भी याद रखना चाहिए, और मैं कभी-कभी ये कहता भी हूँ कि, मेरे पिताजी बस आठ साल के थे जब इंसान पहली बार अंटार्कटिका गया था। कहने का मतलब ये है कि बर्फ से ढका महाद्वीप हाल ही में मानव के अनुभव का हिस्सा बना है। लेकिन अन्य दो स्थान जो बर्फ से ढके हुए हैं, वे हैं आर्कटिक और हिमालय, जिसे अब लोग तृतीय ध्रुव के नाम से जानने लगे हैं। आर्कटिक में रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और आर्कटिक नॉर्डिक देश पहले ही, न केवल आर्कटिक परिषद बल्कि कई अन्य संस्थाओं जैसे कि आर्कटिक सर्कल के साथ सहयोग की एक व्यवस्थित रूपरेखा स्थापित कर चुके हैं। और हमने भारत, चीन और अन्य देशों को प्रेक्षक राज्यों के रूप में मान्यता दी है, लेकिन इस मामले में तथ्य ये है कि हिमालयी क्षेत्र का एक टेबल भी नहीं है।

आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, इस पर आपके, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के बीच संबंध लगभग शून्य हैं। चीन और भूटान के कोई राजनयिक संबंध भी नहीं हैं। और जब हमने कुछ वर्ष पहले मेरे और भारत के पूर्व प्रधान मंत्री के सहयोग से देहरादून में एक सम्मेलन आयोजित किया था, तब भारतीय प्राधिकारी चीन के कुछ बड़े वैज्ञानिकों को प्रवेश करने की भी अनुमति देना नहीं चाहते थे। ऐसा कहके मैं चीन या भारत की निंदा नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं बस राजनयिक वास्तविकता के साक्ष्य के तौर पर आपको बता रहा हूँ। और हालांकि हिमालय के भारतीय पक्ष में लगभग 10,000 हिम नदियाँ हैं, पर मुझे संदेह है कि क्या भारत के पूर्ण प्रशिक्षित हिमनदी विशेषज्ञों की संख्या पर्याप्त है कि हम भारतीय पक्ष के 1000 हिम नदियों के लिए एक विशेषज्ञ को रख सकें। जबकि दूसरी ओर चीन ने विश्व की एक सबसे अभूतपूर्व हिमनदी अध्ययन संस्थान स्थापित कर ली है और उसे सुदृढ़ बना रहा है।

जैसा कि आप जानते हैं यह क्षेत्र एशिया की महान नदियों का उद्भव है। यह देखे बिना कि बर्फ से ढके इस पड़ोस में क्या हो रहा है, भारत, चीन और अन्य देशों के जल भविष्य का विश्लेषण करना असंभव है। हमें पहले ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और अन्य देशों में जल अभाव की सूचनाएं मिलती रही हैं। और चीनी प्राधिकारियों के साथ मेरी चर्चा से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि वे हिमालय और तृतीय ध्रुव की हिम नदियों के पिघलने के परिणामस्वरूप चीन के समक्ष बुनियादी रूप से आने वाली समस्याओं को लेकर डरे हुए हैं। आर्कटिक मॉडल कई मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है और यह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश मध्य पूर्व में सीरिया और यूक्रेन के संघर्ष और प्रतिबंधों के बावजूद, आर्कटिक पर यथोचित रूप से अच्छे और रचनात्मक सहयोग बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। इसलिए, हमने यहाँ पर दिल्ली की अपनी बैठक में न केवल आर्कटिक पर चर्चा की है बल्कि इस बात पर भी चर्चा है कि विज्ञान एवं समझ पर सहयोग का आर्कटिक मॉडल कैसे हिमालयी देशों जैसे कि भारत और चीन और अन्य देशों को एक-साथ आने में मदद कर सकता है। आर्कटिक में दो बहुत शक्तिशाली देश हैं, रूस और अमेरिका और सापेक्षित रूप से पांच छोटे नॉर्डिक देश हैं। हिमालय में दो शक्तिशाली राज्य हैं, भारत और चीन, और फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अन्य छोटे देश भी हैं। इस मायने में ये दर्शाता है कि कैसे छोटे देश शक्तिशाली नेताओं की रूपरेखाओं के अधीन सहयोग कर सकते हैं। आर्कटिक मॉडल बहुत ही दिलचस्प है।

तस्वीरें और टेलीविज़न सूचनाएं कि चरम मौसमी स्वरूपों और बाढ़ों के कारण एशिया के लोगों के साथ क्या हो रहा है, आने वाले वर्षों में अक्सर देखने को मिलेंगी। जिस वर्ष भारत को आर्कटिक परिषद में प्रेक्षक राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था, हमने उसी वर्ष आर्कटिक सर्कल क्यों स्थापित किया इसका एक कारण ये है कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमें एक नए अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता है जहाँ शासनाध्यक्ष, प्रधान मंत्रीगण, राष्ट्रपतिगण, मंत्रीगण, अग्रणी वैज्ञानिकगण, व्यवसाय अग्रणी, और पर्यावरणीय अग्रणी, स्वदेशी लोग और अन्य एक-साथ आ सकें। जैसा कि मैंने सात पहले कहा था, दावोस जैसे एक सम्मेलन में।

दिलचस्प कहानी ये है कि, हम आर्कटिक सर्कल, इस तरह की एक सभा बनाने में सफल भी रहे। अब प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के महीने में आइसलैंड में इसकी बैठक रखी जाती है जिसमें रूस और अमेरिका के अलावा एशिया और यूरोप के सभी बड़े देशों सहित 70 से अधिक देशों से 2000 से अधिक लोग भाग लेते हैं, और पिछले वर्ष आयोजित 180 सत्रों में 700 वक्ताओं ने भाग लिया था। यह 21 वीं सदी में सहयोग का एक आकर्षक मंच बन गया है क्योंकि यह कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से अलग ढंग से आयोजित किया जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत भागीदार, चाहे वो कोई सरकार या थिंक टैंक या संस्थान जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स या कोई व्यावसायिक कंपनी या पर्यावरणीय संगठन हो, कोई भी अपने नाम से एक सत्र का आयोजन कर सकता है और वक्ताओं तथा सामग्री के अर्थों में उनका उस सत्र पर पूर्ण अधिकार होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संवाद का लोकतंत्रीकरण है जबकि अधिकाँश अन्य मामलों में हर कुछ केंद्रीकृत होता है और हर कुछ उस संस्थान के नाम से होता है। हम युवा सक्रियतावादियों को अपने विचार प्रकट करने के लिए वहीँ मंच प्रदान करते हैं जो किसी देश के राष्ट्रपति को देते हैं, और इसने नाटकीय ढंग से बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा, हमने हाल के वर्षों में अन्य देशों में छोटे पैमाने पर फोरम का भी आयोजन किया है, जिसमें 300 से 700 लोगों ने भाग लिया है। अब तक, इस तरह के फोरम संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, ग्रीनलैंड, फरो आइलैंड और कोरिया और चीन में आयोजित हुए हैं। अगला फोरम जून के अंत में बर्लिन में होगा, और फिर ग्रीनलैंड में और साल के अंत से पहले टोक्यो में होगा और फिर अबु धाबी और पेरिस में होगा। आर्कटिक सर्कल एक कार्यशील, गतिशील, विकासशील, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंच बना है और इसलिए मैं आज यहाँ दिल्ली में भारत सरकार को, भारत के विभिन्न संस्थानों तथा इस क्षेत्र में रूचि रखने वाले अन्य लोगों को आर्कटिक सर्कल की सभाओं और फोरम में संलग्न होने के लिए आग्रह करना चाहता हूँ।

कुछ हालिया वक्ताओं में स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस, बान की-मून शामिल हैं जो आर्कटिक सर्कल की सभा में पेरिस जलवायु समझौते की सफलता के बारे में सूचना देने के लिए आए थे। पिछले अक्टूबर में, जॉन केरी, जो पेरिस जलवायु समझौते में प्रत्यक्ष सम्मिलित थे, को आर्कटिक सर्कल पुरस्कार मिला और उन्होंने प्रधान वाच दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हॉलैंड ने अक्टूबर 2015 में प्रधान वाच दिया। यह एकमात्र भाषण था जो उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से दो माह पहले दिया था। सम्मेलन से कुछ माह पूर्व, मैंने, उनके कुछ कहने से पहले, उनसे सबसे तेजी से पिघलती हिम नदी दिखाने के लिए ले जाने का वादा किया। मैंने हेलिकॉप्टर को वहां नहीं उतरवाने का फैसला किया जहाँ हिम नदी का छोर था बल्कि वहां जहाँ से उस हिमनदी ने जन्म लिया था। और मैंने राष्ट्रपति और उनके पूरे परिचारकगणों और फ्रांसीसी मीडिया को लम्बे समय तक चलाया, काले रेत पर, चट्टानों पर, आर्द्र भूमि पर, जब तक कि वे आखिरकार हिम नदी के छोर पर न पहुँच गए, जहाँ वो अब मौजूद है। और जैसा कि क्रिस्टीना फिगरर्स ने कहा था, उस हिम नदी पर जाने और आपके साथ पैदल चलने से पहले, उनका राजनीतिक मस्तिष्क निश्चित ही जलवायु वार्ता में खोया हुआ था। लेकिन वहां से वापस आने के बाद, उनका ह्रदय और आत्मा भी उसी में खो गया था। मेरे दोस्तों, हिम नदियों को गायब होते देखना एक अभूतपूर्व अनुभव है। और इसलिए जब आपके प्रधानमंत्री ने पिछले चुनावों से कुछ दिनों पहले हिमालय गए और वहां पर हिमालय की एक हिमनदी की छोर पर बैठ कर भारत के भविष्य और दुनिया के भविष्य का चिंतन किया, मुझे लगा कि इससे लोगों को एक असरदार सन्देश जाएगा। मैं भारतीय राजनीति में किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे यह दिलचस्प लगा कि ये वो आखरी तस्वीर थी, जो वे भारतीयों को अपनी अगली सरकार चुनने के लिए चुनाव में मतदान करने के लिए जाने से पहले भेजना चाहते थे।

आर्कटिक सर्कल अपने अपेक्षाकृत कुछ वर्षों में, एक ऐसा मंच बन गया है जहाँ प्रमुख नेताओं और देशों को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिलता है। दो साल पहले, जापान के भूतपूर्व विदेश मंत्री ने अपना प्रधान वाच 'आर्कटिक को लेकर जापान का दृष्टिकोण' प्रस्तुत करने के लिए रेयकजाविक की यात्रा की थी। और मैंने अब इसी तरह अपने दौरे के दौरान भारत सरकार के उच्च स्तरीय मंत्रियों को आर्कटिक सर्कल की अगली सभा में उपस्थित होने और आर्कटिक पर भारतीय नीतियों, दृष्टि और भारतीय परियोजना पर इसी तरह का एक प्रधान वाच देने के लिए आमंत्रित किया है, जैसा कि फ्रांस के राष्ट्रपति और जापान के विदेश मंत्री, रूस के यमालो-नेनेट्स के युवा गवर्नर ने हाल के वर्षों में किया है। यमालो-नेनेट्स 21 वीं सदी का एक प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र है। अनुमान है कि इस दशक के अंत से पहले, यह दुनिया में 20% एलएनजी का उत्पादन करेगा। इसका अर्थ है कि गवर्नर के पास क़तर जैसा ही एक क्षेत्र है जो वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के लिए बेहद महत्वपूर्व है। जो लोग यह नहीं समझते हैं कि रूस और टुन्ड्रा किस तरह एशिया, यूरोप और संभवतः भारत की ऊर्जा पॉवरहाउस में रूपांतरित होती जा रही है, उन्हें स्वयं इस क्षेत्र के दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि यमालो-नेनेट्स में क्या हो रहा है। मुझे कुछ साल पहले सबेटा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जहाँ लगभग 10 साल पहले कुछ नहीं हुआ करता था, वस्तुतः जमे हुए टुन्ड्रा के अलावा कुछ भी नहीं हुआ करता था, कोई इंसान, नोई बस्ती, कुछ नहीं। अब वहां पर बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है जहाँ आइसब्रेकर्स के साथ कोरियाई टैंकर्स संभावी रूप से रूस की एलएनजी को एशिया और यूरोप दोनों जगहों पर पहुंचा रहे हैं।

मैं अपने अमेरिकी दर्शकों के साथ कभी-कभी मज़ाक करता हूँ और पूछता हूँ कि आपमें से कितनों ने सबेटा का नाम सुना है? आम तौर पर सैकड़ों दर्शकों में से एक या दो लोगों को इसके बारे में मालूम होता है, अधिकतर पश्चिमी और एशियाई जगत ने सबेटा के बारे में नहीं सुना है। लेकिन यह 21 वीं सदी का एक सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र है। और राष्ट्रपति पुतिन ने आगामी वर्षों में इस रूपांतरण की अगुआई करने के लिए 30-40 साल के इस युवा को चुना था।

आर्कटिक सर्कल ने अपनी वार्षिक सभाएं न केवल रेयकजाविक में आयोजित की हैं बल्कि चीन, सिंगापुर, अलास्का, कोरिया, वाशिंगटन, फरो आइलैंड, स्कॉटलैंड, क्यूबैक, ग्रीनलैंड में भी आर्कटिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य तथा सहयोग और विज्ञान और राजनय पर चर्चाएँ आयोजित की गई हैं और आगामी महीनों में बर्लिन, ग्रीनलैंड, जापान, और अबु धाबी में भी ये सभा आयोजित होंगी। एशिया से बाहर, हिमालय तृतीय ध्रुव क्षेत्र पर प्रथम प्रमुख अंतर-शासकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करवाने के लिए मैंने संयुक्त अरब एमिरात की सरकार के साथ हल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इस प्रस्तुति के माध्यम से आज मैं आप सभी को इस प्रयत्न में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूँ कि यह न केवल बौद्धिक रूप से दिलचस्प होगा बल्कि यह आर्कटिक और संभवतः हिमालय के माध्यम से आपकी आँखें भी खोलेगा, कि हम अपने समय का एक सबसे दिलचस्प भूराजनीतिक रूपांतरण देख रहे हैं। यदि हम वास्तव में भारत का भविष्य और विश्व में आपकी जगह को समझना चाहते हैं, तो आपको कम से कम आंशिक रूप से उस समझ को आर्कटिक और हिमालय के साथ जोड़कर देखना होगा। तो दोस्तों इस तरह मैं औपचारिक रूप से आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय गतिशील, लोकतान्त्रिक और खुले सहयोग के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जहाँ आपमें से हर कोई एक निश्चित भूमिका निभा सकेंगे जो आपके अनुसार इस प्रयोजन के लिए उचित हो। और मैं कभी-कभी यह भी कहता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने या मेरे सहकर्मी ने कितनी चतुराई से संगठनात्मक प्रयास किए हैं, पर हम इस पैमाने, इस आयाम, इस गतिशील विकास के इस वैश्विक मंच का निर्माण नहीं कर पाते यदि विश्व में रूपांतरण की भूमिगत लहर न फैली होती, जिसने इन सभी लोगों को साथ लाया है, और एहसास करवाया है कि एक तरफ आर्कटिक और दूसरी तरफ हिमालयी तृतीय ध्रुव अब हमारे देशों के भविष्य और हमारे ग्रह के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। और आज बाद में, मेरे एक अच्छे मित्र आर्कटिक सर्कल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेगफिनूर स्वेनहॉर्सन इस बारे में अधिक विस्तार से बताएंगे कि यह हिमालयी तृतीय ध्रुव प्रयास के साथ कैसे जुड़ा है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, चूंकि मैंने अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन के कई वर्षों में भारत से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए भारतीय समाज, सरकार, व्यवसाय और वैज्ञानिक समुदाय के बहु क्षेत्रों से इस आर्कटिक प्रयास में और इस नई दिलचस्प वैश्विक यात्रा में भारत की ओर से बढ़ा हुआ जुड़ाव देख कर मुझे ख़ुशी होगी, जिसके बारे में मैं आज यहाँ अपने व्याख्यान के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद।

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

एक शानदार व्याख्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महामहिम। और ऐसा शायद कभी-कभी ही होता है कि कोई व्याख्यान उन सभी अपेक्षाओं की पूर्ती करती है जो सप्रू हाउस के संक्षेप व्याख्यान में होती है, क्योंकि यह हम सभी के लिए बहस के प्राचलों का दायरा बढ़ाता है। मैं इसे सारांशित करने कि कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन कम से कम, मेरे लिए तीन महत्वपूर्ण बिन्दुएँ हैं, पहला, आर्थिक मायनों, भू-आर्थिक अर्थों और भू-सामरिक अर्थों में आर्कटिक के महत्व को रेखांकित करना, सभी कारणों के लिए और सबसे स्पष्ट कारण, बेशक, सुएज़ की तरह ही एक नई परिस्थिति, एक नए परिदृश्य का उभरना है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है।

दूसरा, बेशक, जलवायु परिवर्तन की चुनौती है। और आपने इसे, औसत समुद्र स्तर में दो मीटर की वृद्धि और सभी तटीय एशिया के लिए इसके निहितार्थों और पूरे एशिया में मानसून के अर्थों में बहुत ही सुचित्रित ढंग से वर्णित किया। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है, इस परिषद जैसे संस्थानों के लिए, और क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में सोचते अन्य संस्थानों के लिए हिमालयी बिरादरी का आर्कटिक मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने कहा, ये सभी तीन बिन्दुएँ बहस के प्राचल का दायरा बढ़ाते हैं। हमारे लाभ के लिए इस अद्भुत अनिमेटेड व्याख्यान के लिए मैं आपको धन्यवाद और मुबारकबाद दोनों देना चाहूँगा।

मुझे लगता है कि हमारे पास सवालों के लिए थोड़ा समय है। इसलिए आपकी अनुमति से, मैं अब चर्चा के लिए मंच को खोलूंगा और मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप अपने प्रश्नों और टिप्पणियों को संक्षिप्त रखें। और पहले खुद की पहचान

बताएं। हाँ, डॉ. बालाकृष्णन, राजदूत बालाकृष्णन, एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भी हैं, और ये हमारे सिस्टर अनुसंधान संस्थानों में कई कार्यक्रमों का नेतृत्व करते हैं।

डॉ. भास्कर बालाकृष्णन

महामहिम, आर्कटिक परिषद में, छह प्रेक्षक हैं जो स्वदेशी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आर्कटिक परिषद में उनकी भूमिका कैसी रही है?

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

शायद हमें एक साथ तीन या चार सवाल ले लेने चाहिए।

ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन: आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति

हाँ, ज़रूर।

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

जी महोदय।

ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन: आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति

हाँ।

ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन: आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति

क्या माइक ऑन कर सकते हैं?

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

हाँ।

कनिष्क गुप्ता: प्रसार भारत में सामरिक मामलों के ब्लॉगर

सुप्रभात महोदय। मेरा नाम कनिष्क गुप्ता है और मैं प्रसार भारत में सामरिक मामलों का एक ब्लॉगर हूं। महोदय, मेरा प्रश्न है, आर्कटिक क्षेत्र में हिम नदियों के पीछे खिसकने और बर्फ के पिघलने के संबंध में हम पहले ही सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। तो चीन, रूस और अमेरिका वहां पर सैन्य प्रतिष्ठान क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रूस ने पिछले साल वोस्तोक -18 नाम का एक बड़ा अभ्यास किया था, और उस क्षेत्र में 40 से अधिक आइसब्रेकर और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं एवं और भी आइसब्रेकर आ रहे हैं, पर हमें पहले ही बर्फ पिघलने के संबंध में सुरक्षा जोखिम है। तो वहां सैन्य प्रतिष्ठान क्यों किए गए हैं?

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

हाँ

अनुराग बिसेन

सुप्रभात महोदय। मुझे 2017 में [inaudible 73:36] आपसे मिलने की प्रसन्नता - सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आपने वो सवाल [inaudible 73:38] पूछा था। मेरा नाम अनुराग बिसेन है। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का प्रतिनिधि हूँ। महोदय, मेरा सवाल ये है कि आर्कटिक की पिछला मंत्रीस्तरीय बैठक ऐसी पहली सभा थी जिसमें कोई संयुक्त घोषणा नहीं की गई थी, महोदय, कोई संयुक्त घोषणा नहीं की गई थी।

ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन: आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और आर्कटिक सर्कल के चेयरमैन

हाँ।

अनुराग बिसेन

शायद इसलिए क्योंकि अमेरिका घोषणा में जलवायु परिवर्तन को शामिल करने को लेकर सहमत नहीं था। महोदय, आपको क्या लगता है कि बड़ी शक्ति की इस दुश्मनी का आर्कटिक के छोटे राज्यों के चिंताओं पर क्या असर होगा। धन्यवाद।

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

एक और। हाँ, डॉ. बनर्जी?

स्तुति बनर्जी

धन्यवाद महोदय। मेरा नाम डॉ. स्तुति बैनर्जी है, मैं परिषद की एक शोधकर्ता हूँ। महोदय, मेरा सवाल है कि चीन के उद्भव और आर्कटिक में चीन की संलग्नता को लेकर कई चिंताएं हैं। तो आप, जैसा कि आपने अपने परिचय में कहा, आर्कटिक के संबंध में पर्यावरणीय चिंताओं के वक्ता रहे हैं। तो आर्कटिक परिषद के देशों में एक मतभेद है, जिनमें से कुछ देश पर्यावरण को एक प्रमुख कारण के रूप में देखते हैं और जबकि अन्य प्रभुसत्ता का दावा और सैन्यकरण में जुटे हुए हैं। तो मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आपकी राय में इन दोनों मुद्दों की ओर काम करते देशों का भविष्य क्या होगा? धन्यवाद।

ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन: आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति

खैर, इन बेहतरीन सवालों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरे व्याख्यान की प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि भारत में विदेश नीति के बारे में बात करना हमेशा से एक चुनौती रही है, क्योंकि आप उन कुछ देशों में से एक हैं जो विदेशी मामलों के बारे में बात करते हुए अब भी बहुत सख्त, कड़ी, बौद्धिक परंपरा को बनाए रखते हैं। अन्य देश में ऐसी चीजों से बचना बहुत आसान है। इसलिए मैं आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने वाले किसी भी व्यक्ति की असली परीक्षा भारत में होती है, वह सूचित भारतीय दर्शकों की आलोचना और टिप्पणियों के अधीन होता है, मैंने हमेशा से आप लोगों के बौद्धिक दृष्टिकोण की सराहना की है। मैं जानता हूँ कि यह कभी-कभी भारत सरकार के निर्णय निर्माताओं के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। लेकिन यह भारतीय संस्कृति के आकर्षक पहलुओं में से एक है।

आर्कटिक परिषद में स्वदेशी लोगों की भूमिका ऐतिहासिक महत्व की है। मेरा मानना है कि आठ आर्कटिक राज्यों के शासकीय निकाय में आर्कटिक परिषद एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसने स्वदेशी लोगों के अंतर्निहित लोकतांत्रिक अधिकार को पहचाना है कि आर्कटिक के भविष्य को लेकर उन्हें भी अपनी बात सामने रखने का अधिकार है। शायद, प्राथमिक रूप से, इस आधार पर कि ये लोग सदियों से या इन राज्यों के अस्तित्व में आने से हजारों साल पहले से आर्कटिक में मौजूद थे, रूस का संघटन अपेक्षाकृत रूप से युवा है जैसा कि हम जानते हैं केवल कुछ दशकों पुराना है। संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ सौ साल पुराना है, कनाडा उससे भी कम साल पुराना है। आइसलैंड 1944 में एक गणराज्य बना और नॉर्वे केवल कुछ दशकों पहले एक गणराज्य बना। तो हमारे पास अपेक्षाकृत रूप से युवा राज्य हैं, जो स्वदेशी लोगों से यह कहना चाहते हैं कि आप एक बार अपने क्षेत्र का भविष्य बनें।

और अपने विश्वास से, हमने स्वदेशी लोगों के अधिकार को पहचाना है और इसलिए विश्व के अन्य हिस्सों के कई स्वदेशी समुदाय आर्कटिक मॉडल से अपेक्षा रखते हैं, ताकि वे अपने स्वयं के भविष्य को लेकर अपनी बात रखने का अधिक दावा कर सकें। मैं कभी नहीं भूल सकता कि 10 साल पहले, जब मैं बांग्लादेश में था और पर्यावरण मंत्री ने मुझे जलयात्रा के लिए आमंत्रित किया था, यह दिखाने के लिए कि कैसे समुद्र का बढ़ता स्तर बांग्लादेश के भविष्य को प्रभावित करेगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लेकिन बाद में यह पता चला कि मंत्री जी 4000 या 400,000 लोगों के एक कबीले के राजा भी थे।
और जब हम नाव पर बैठ कर इस बात की चर्चा कर रहे थे या देख रहे थे कि बांग्लादेश में समुद्र का स्तर कैसे बढ़ रहा है, तब उन्होंने आर्कटिक परिषद के स्वदेशी लोगों के अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा शुरू कर दी, जिसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। और उन्होंने कहा, कि वो भी बांग्लादेश की शासकीय प्रणाली के अंतर्गत अपने कबीले या उसे जो कुछ भी कहते हैं या लोगों को भी वहीं अधिकार दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि चीन, भारत और हिमालयी क्षेत्र के अन्य देशों के सामने भी ये एक चुनौती है।
आप हिमालय के स्वदेशी समुदायों को किस हद तक सशक्त करने वाले हैं, उसी तरह जिस तरह हमने आर्कटिक में किया है। और मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मैं चीन के हुनान में गया था, मैं पहाड़ों पर गया जहाँ की बारह में से चार हिम नदियाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। और उस समुदाय की मेयर ने, जो एक बहुत ही मजबूत महिला थीं, चीनी विदेश मंत्रालय के अध्यक्ष, जो मेरे साथ थे, की उपस्थिति में एक वृहद व्याख्यान देना शुरू कर दिया और इस बात की शिकायत कर रही थीं कि उनके क्षेत्र के जल प्रणाली और उनके गाँव के साथ क्या हो रहा है, बीजिंग की सरकार समझ नहीं पा रही है।
तो मुझे लगता है कि आप बिलकुल सही हैं। भारत, अन्य हिमालयी देश, और आर्कटिक के देशों के लिए भी एक बड़ा सवाल ये है कि जो लोग इस क्षेत्र में सैकड़ों और हजारों साल से रह रहे हैं और जो परिवर्तनों के नाटकीय परिणामों को देशों की राजधानियों में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक झेलेंगे, उनकी भूमिका क्या होगी।

दूसरा सवाल सुरक्षा चिंताओं पर है, हाँ, मैं जानता हूँ कि सुरक्षा को लेकर बहुत चिंताएं हैं, मैं इसे आर्कटिक में सुरक्षा परिवर्तनों के प्रति मीडिया का अत्यधिक प्रचार कहूँगा। लेकिन इसे एक भय-प्रसारक न बनने दें। मैंने अपने व्याख्यान में बताया कि शीत युद्ध के दौरान, यह विश्व की सबसे अधिक सैन्यकृत क्षेत्रों में से एक था। अमेरिकियों ने अपने आइसलैंड के बेस को बंद कर दिया था। ग्रीनलैंड के कई बेस भी बंद हो गए थे। और बेशक, सोवियत संघ के पतन के बाद आर्कटिक में रूसी सैन्य उपस्थिति की गुणवत्ता अवांछित थी। मैं यह नहीं कहता कि ये वास्तव में मंद हो रही थी, लेकिन कुछ हद तक ऐसा ही था।

तो रूस जैसे देश के लिए एक ऐसे क्षेत्र, जिसके तहत सात समय क्षेत्र आते हैं और जो रूस के भविष्य के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, के लिए अपनी क्षमताओं का निर्माण सुस्पष्ट है। लेकिन मैंने पिछले साल कहा था कि हमें इस संबंध में आर्कटिक में एक समझौते में प्रवेश करने की आवश्यकता है कि आर्कटिक में कौन सी निर्माण क्षमताएं स्वीकार्य होंगी, अन्यथा उठाया गया हर एक कदम आतंक फैलाने का आधार होगा। क्योंकि यह समझा जा सकता है महत्वपूर्ण देशों, चाहे अलास्का का संयुक्त राज्य अमेरिका हो या आर्कटिक का रूस हो, के लिए निश्चित क्षमताएं होना आवश्यक है। और जहाँ तक चीन का सवाल है, तो कम से कम, मुझे नहीं लगता कि हमें अब तक कोई ऐसा साक्ष्य मिला है जिससे यह साबित होता हो कि चीन आर्कटिक में सैन्य रूचि रखता है, अगर यहाँ पर किसी को ऐसे साक्ष्य के बारे में जानकारी है तो मैं भी जानना चाहूँगा।

तो, अब तक चीन ने आर्कटिक में अपनी रूचि को आकार देते हुए मुख्य रूप से आर्कटिक में अपनी गहन आर्थिक रूचि और ऊर्जा रूचि दिखाई है, और, बेशक, आर्कटिक में प्रबल वैज्ञानिक रूचि भी दिखाई है। लेकिन अब तक, चीन ने किसी भी यथोचित सैन्य बोध में आर्कटिक में प्रवेश नहीं किया है, और न ही जापान और न ही कोरिया ने किया है। हम आर्कटिक में जो भी सैन्य परिवर्तन देखते हैं, वो एक तरफ रूस की ओर से और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से है। और साफ-साफ कहूँ तो, जहाँ तक अमेरिका -- सवाल है, हमें अब भी ये देखना बाकि है कि क्या कांग्रेस रूसी आर्कटिक या यहाँ तक कि ग्रीनलैंड में कोई यथोचित सैन्य निर्माण के लिए आवश्यक धन प्रदान करेगी या नहीं, जब वे स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहते हैं और यहीं कारण है कि पहली बार विदेश विभाग ग्रीनलैंड में एक दूतावास कार्यालय खोल रहा है। अब तक आइसलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जो ग्रीनलैंड में राजनयिक रूप से उपस्थित है।

अब अमेरिका का विदेश विभाग इस वर्ष ग्रीनलैंड में अपना एक कार्यालय खोल रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह बदलेगा नहीं, लेकिन अब तक, मुझे नहीं लगता कि आर्कटिक में कोई सैन्य प्रतिस्पर्धा या भय-प्रसारक सैन्य निर्माण है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भारत को सैन्य दृष्टि से आर्कटिक में अपनी उपस्थिति के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन यह बदल भी सकता है, कौन जानता है, लेकिन अब तक, इसका कोई साक्ष्य नहीं है।
और आप बिलकुल सही बोल रहे हैं। आर्कटिक में बनी किसी भी सैन्य अवसंरचना के खतरे की तुलना में हिम नदियों के पिघलने का खतरा, आर्थिक सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, यहाँ तक की जलवायु सुरक्षा के खतरे कहीं अधिक हैं। और आप -- मैं फ्रांस के राष्ट्रपति हॉलैंड को आइसलैंड की हिम नदियाँ क्यों दिखाने ले गया था, इसका एक कारण ये है कि जब तक हिम नदी के सामने न खड़े हों, तब तक आप जो कुछ भी हो रहा है उसकी शक्ति, उसकी गंभीरता को नहीं समझ सकते। हम उन्हें हिम नदी पर ले गए, और उन्हें वहां अकेला छोड़ दिया, ताकि वे हिम नदियों के टूटने की आवाज़ सुन सकें। क्योंकि हिम नदियों के पिघलने पर आवाज़ आती है, इसलिए मैं इसे कभी-कभी जलवायु परिवर्तन का संगीत कहता हूँ। और इसे अपने कानों से सुनना अपने-आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व अनुभव है, कि कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और तब आप समझते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैन्य क्षमता क्या है, इस बल की ताकत, चाहे ग्रीनलैंड में हो, हिमालय या कहीं और हो, इतनी शक्तिशाली है कि देशों की सैन्य क्षमताएं, यहाँ तक की अमेरिका या रूस की सैन्य क्षमताएं इतनी नहीं हैं कि वे इसे रोक सकें। एकमात्र ऐसी चीज जो इसे रोक सकती है, वो पूरी दुनिया में हर जगह व्यापक ऊर्जा रूपांतरण लाना है।

पिछले वर्ष आर्कटिक परिषद की मंत्रीस्तरीय बैठक में संयुक्त घोषणा न होने का कारण बेशक यह था कि ट्रम्प सरकार ऐसे किसी भी घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती थी जिसका मुख्य मुद्दा जलवायु परिवर्तन हो। लेकिन यह भी बहुत दिलचस्प है कि ट्रम्प प्रशासन वह पहला अमेरिकी प्रशासन है जिसने अपने पहले कार्यकाल में ही आर्कटिक में रूचि दिखाई है। सम्मानपूर्वक कहना चाहूँगा कि ओबामा को अपने पहले कार्यकाल में आर्कटिक में कोई रूचि नहीं थी। उनकी सरकार में हिलरी एकमात्र ऐसी व्यक्ति थीं जो आर्कटिक के महत्व के बारे में बात किया करती थीं और उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे विदेश विभाग के प्रत्येक अधिकारी ने उनसे कहा था कि उन्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, अमेरिका के सचिव को अन्य मामलों से सरोकार रखना चाहिए।

लेकिन वो आर्कटिक परिषद की मंत्रीस्तरीय बैठक में भाग लेने वाली पहली विदेश सचिव बनीं। लेकिन, बेशक, ट्रम्प, पोम्पियो ने जो भाषण दिया था वो बहुत ही परिवर्तनकारी था। यह इस तरह का पहला भाषण था, जिसके माध्यम से आर्कटिक के मंत्रीस्तरीय बैठक में भूराजनीतिक तनाव को इस पैमाने पर प्रस्तुत किया गया था। और उन्होंने हम सभी को चीन के खिलाफ चेतावनी दी थी, यह कहते हुए कि चीन आर्कटिक का कोई करीबी राज्य नहीं है, मूल रूप से यह कहना चाहते थे कि इस समूह में चीन की कोई भूमिका नहीं है। पर कोई अन्य आर्कटिक राज्य उनसे सहमत नहीं हुआ। उसके एक दिन बाद शंघाई में हमारा आर्कटिक सर्कल फोरम था। और स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा और अन्य देशों के कुछ प्रमुख प्रतिनिधि फ़िनलैंड की मंत्रीस्तरीय बैठक से सीधे शंघाई के आर्कटिक सर्कल फोरम में पहुंचे थे।

और कोई भी इससे सहमत नहीं हुआ। और अब हम पहली बार MOSAiC नामक वैज्ञानिक सहयोग देख रहे हैं, जिसमें चीन, कोरिया, जापान, कनाडा और अन्य देशों समेत 17 देशों ने मानव के इतिहास में पहली बार उत्तरी ध्रुव के आस-पास 12 महीनों का शोध अभियान चलाया है। हम यहाँ उत्तरी ध्रुव में शर्दी के महीनों के दौरान कभी-भी डेटा, वैज्ञानिक डेटा संग्रह करने में सक्षम नहीं रहे हैं। यह ऐतिहासिक महत्व का है और वैज्ञानिक नतीजे देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। शंघाई के फोरम में जर्मन के एक प्रतिनिधि ने घोषणा की थी कि चीन की प्रतिभागिता के बिना ऐसा करना संभव नहीं था। तो इस तरह आर्कटिक के कुछ अन्य राज्य हैं जिनका कहना है कि हमें एशियाई देशों की प्रतिभागिता के बिना आर्कटिक में आवश्यक नतीजे नहीं मिल सकते थे।

तो दिलचस्प सवाल यह होगा कि अगर ट्रम्प पुनः निर्वाचित होते हैं, तो वे इस पर अगली क्या कार्यवाही करेंगे? अमेरिकी प्रणाली में, अलास्का रक्षा मुख्य रूप से रक्षा विभाग के अधीन पेंटागन के उत्तर में तट रक्षकों का विषय रहा है। पर ये बदल रहा है। अब इसमें पेंटागन की रूचि बढ़ रही है। अमेरिका ग्रीनलैंड में अपना कार्यालय क्यों खोल रहा है इसका एक कारण ये है कि वो ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति को भी बढ़ाएंगे।

तो बेशक यह संभव है कि ट्रम्प के द्वितीय कार्यकाल में हमें इसमें तीव्रता देखने को मिलेगी। यदि डेमोक्रेट्स जीतते हैं, तो मुझे लगता है कि सबके सामने खुला सवाल ये होगा कि अब आगे क्या होगा? लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह चीन को सैन्य अर्थों में आर्कटिक में लेकर आएगा। यह प्राथमिक रूप से एक तरफ मापेगा कि रूसी क्या कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें स्वीकार करना होगा और अवगत होना होगा कि अमेरिका में रिपब्लिकन ही नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक नेताओं ने भी 21 सदी में चीन और अमेरिका के बीच इस बड़े खेल को सही या गलत के नज़रिए से देखा है, जैसा कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति के संवाद और भारत तथा अमेरिका के बीच नए संबंधों से जानते हैं।

और ट्रम्प प्रशासन ने क्या किया है कि उसने 21 सदी के इस बड़े खेल की रूपरेखा में आर्कटिक को शामिल कर लिया है। तो, जैसा कि मैंने कल, परसों भारत के मंत्रियों को कहा था, अमेरिका के साथ आपके द्विपक्षीय चर्चाओं में, अभी या बाद में, अमेरिका आर्कटिक का मुद्दा जरूर छेड़ेगा या हो सकता है कि छेड़ चुका हो। और आपसे पूछेगा कि यह चीन के साथ आपके संबंधों, रूस के साथ आपके संबंधों और अन्य एशियाई देशों के साथ आपके संबंधों और अमेरिका के साथ आपके संबंधों पर क्या असर डालता है। यदि इस चुनाव में डेमोक्रेट्स जीतते हैं, तो हालांकि यह एक बहुत ही खुला – खुला सवाल होगा। मैं आपको पहले ही MOSAiC अभियान के बारे में बता चुका हूँ। यदि आप कोरिया के सीओल और शंघाई में स्थित ध्रुवी संस्थान की आशा करते हैं तो यह बहुत ही प्रभावशाली है।

मैंने अपने नॉर्डिक देशों के दोस्तों से कहा, भले ही हम औपचारिक रूप से आर्कटिक राज्य हैं, पर फिर भी हम में से किसी के भी देश, चाहे स्वीडन, नॉर्वे, फ़िनलैंड, डेनमार्क या आइसलैंड हो, के पास कोरियाई और चीनियों के ध्रुवी संस्थानों, उनके शोध वेसेल और उनकी प्रौद्योगिकी की तुलना में कुछ भी नहीं है। कोरिया ने दो साल पहले कोरिया पोलर विजन 2050 को मंजूरी दी, उन्होंने ध्रुवी क्षेत्र में संलग्नता के लिए 30 वर्षों की योजना बनाई है।

तो, जब लोग मुझसे चीन और आर्कटिक की बात करना चाहते हैं, मैं अक्सर बातचीत को कोरिया और आर्कटिक पर ले जाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इस पर चिंतन करना अधिक दिलचस्प है, क्योंकि केवल चीन, रूस और अमेरिका ही नहीं बल्कि अधिक विस्तृत पैमाने पर वैश्विक रूपांतरण हो रहा है। मैंने इस चीज को पहली बार अपना राष्ट्रपति-काल समाप्त होने से एक साल पहले अनुभव किया था जब मैंने भाग लिया था, नहीं-नहीं उससे भी पहले। मेरे विचार में शायद 2012 में, जब मैं दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक सम्मेलन में गया था। तब मुझे कोरियाई संसद के कुछ सदस्यों से मिलने के लिए कहा गया जो तब उस समय के नव निर्वाचित राष्ट्रपति के प्रतिनिधि थे।

पर मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो मुझसे क्या बात करना चाहते थे। मुझे ये बहुत ही अजीब लगा कि आखिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? लेकिन फिर बाद में पता चला कि दक्षिण कोरिया के नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने उन्हें मुझसे मिलने को कहा था ताकि मैं आर्कटिक परिषद में एक प्रेक्षक राज्य के लिए कोरियाई सदस्यता का समर्थन कर सकूँ। जबकि, उसी समय सिंगापुर के प्रधान मंत्री राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात करने के लिए दौरे पर जा रहे थे। और जैसी कि प्रथा है, सिंगापुर के सभी अधिकारियों और वाशिंगटन के सभी अधिकारियों की तैयारी बैठक थी ताकि उनकी बैठक के लिए तैयारी

की जा सके। तो, इस तैयारी बैठक के अंत में, सिंगापुर के अधिकारियों ने वाइट हाउस के अधिकारियों से कहा कि हमें बेशक मालूम है कि प्रधान मंत्री महोदय राष्ट्रपति से आर्कटिक के बारे में बात करना चाहते हैं।

और वाशिंगटन के वाइट हाउस के लोग बस हसने लगे, उन्हें लगा कि ये मज़ाक है। तो जब बैठक शुरू हुई, सिंगापुर के प्रधान मंत्री ने सबसे पहली बात यह उठाई कि सिंगापुर को आर्कटिक परिषद में एक प्रेक्षक राज्य बनाने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा से समर्थन माँगा। लेकिन वाइट हाउस में जिन लोगों ने इसे मज़ाक समझ कर हंसी में उड़ा दिया था, उन्होंने राष्ट्रपति को इसके लिए तैयार नहीं किया था, या ये भी नहीं बताया था कि यह मुद्दा एजेंडा में होगा। तो वो इसके लिए बिलकुल तैयार नहीं थे।

और मैं आपको ये दो कहानियाँ सुना रहा हूँ। एक तो मेरा खुद का अनुभव है, और दूसरा ओबामा जी का अनुभव है और इसके माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि यह रूपांतरण कितने हाल में हुआ है। और इन दो बैठकों के बाद जो कुछ भी हुआ है उसका पैमाना हमारे नज़रों के सामने होने वाले उच्च गति भूराजनीतिक रूपांतरण का सबसे दिलचस्प साक्ष्य है। और भारत को सुनिश्चित रूप से, और स्पष्ट रूप से तथा बड़े पैमाने पर उस रेलगाड़ी पर सवार होने की आवश्यकता है।

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

धन्यवाद, हमारे पास एक और राउंड के लिए समय है, महामहिम यदि आप चाहें तो?

ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन: आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति

जरूर।

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

हाँ। भूराजनीतिक, आर्थिक संभावनाओं को संतुलित करने के बारे में भी एक सवाल था?

ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन: आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति

हाँ, मैं उसका जवाब दूंगा।

संजीव चतुर्वेदी: दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय

महामहिम। मेरा नाम संजीव चतुर्वेदी है और मैं नई दिल्ली के दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय से हूँ। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका व्याख्यान सुनने और सीखने का अवसर मिला। मेरा सवाल उस संबंध में है जिसे आर्कटिक सामाजिक वैज्ञानिक, ध्रुवी सामाजिक वैज्ञानिक आर्कटिक विरोधाभास कहते हैं। क्योंकि हम एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण के अंतर्गत इन रूपांतरणों को देख रहे हैं जिसे ऐन्थ्रोपोसीन कहते हैं, हम अक्सर इस लगातार परिवर्तनशील आर्कटिक के बारे में सोचते हैं। और विरोधाभास इस तथ्य से संबंधित है कि एक ओर हम उस भूमिका को देख रहे हैं जो जीवाश्म ईंधनों ने ग्लोबल वार्मिंग में निभाई है। वहीँ दूसरी ओर आर्कटिक में छीना-झपटी का एक उत्प्रेरक ये अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मानचित्र और तेल की संभावना है, जिसके आर्कटिक में होने की बात कर रहे हैं।

तो मेरा सवाल है कि भविष्य को देखते हुए और तीनों ध्रुवों को देखते हुए, जो इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिक के पिघलने के परिणामस्वरूप बहुत बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि क्या आर्कटिक जुड़ाव के बारे में विभिन्न व्याख्या के मेनू में हमें पारिस्थितिकी की व्याख्या, ऐन्थ्रोपोसीन की व्याख्या को महत्व नहीं देना चाहिए? और इस आर्कटिक विरोधाभास से

किस तरह का असमंजस पैदा हो सकता है और इस आर्कटिक विरोधाभास को संबोधित करने के लिए हमें किस प्रकार के राजनय और वैज्ञानिक राजनय की आवश्यकता होगी? धन्यवाद।

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

हाँ, हाँ।

हिमांशु चौधरी: राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय

सुप्रभात महोदय। मैं राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय से हिमांशु चौधरी हूँ। ऊर्जा, वाणिज्य, पर्यावरण और जल सुरक्षा के चार मुख्य पहलुओं को देखते हुए, और आपके परिप्रेक्ष्य में, इंटरनेट, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित किसी भी चीज पर कोई टिप्पणी देने में आपकी हिचकिचाहट के बावजूद, आपकी राय में भारत की आर्कटिक रूचि किसमें निहित होनी चाहिए, क्या रेलगाड़ी को स्टेशन से रवाना होना शुरू होना चाहिए और यदि हाँ तो कब?

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

हाँ, वहां पीछे बैठीं देवी।

अज्ञात वक्ता

मेरा नाम शालोग्रा है। और मैं ध्रुवीय मुद्दों पर एक थिंक टैंक से हूँ। हम एक दशक से काम कर रहे हैं जिसे अब सागा के नाम से जाना जाता है। मेरा सवाल है कि आपने दोहराया कि हमें चीन की उत्सुकता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आइसलैंड, फ़िनलैंड और स्वीडन, उनकी एक वेधशाला है जो '17, '18 -- '16, '17, '18 में आई है, और सभी का कार्य संचालन आरम्भ हो चुका है, आइसलैंड में भी एक वेधशाला है जिसका संचालन हाल में शुरू हुआ है, जिसे देख कर लोगों का कहना है कि शायद नाटो एयरस्पेस पर निगरानी रखी जा रही है। और कई लोग इस पर लिख भी रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है?

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

कि अंतरिक्ष की वेधशालाओं में वेधशालाएं, सैन्य वेधशालाएं स्थापित हैं। और हैं – कई पैमाने की प्रमुख गतिविधियाँ हो रही हैं।

ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन: आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति

हाँ, ज़रूर, ज़रूर। आप आइसलैंड की वेधशाला के बारे में बात कर रही हैं?

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

हाँ, आइसलैंड की वेधशाला।

ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन: आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति

हाँ।

अथर ज़फर: विश्व मामलों की भारतीय परिषद

धन्यवाद महोदय। मैं डॉ. अथर ज़फर हूँ और मैं विश्व मामलों की भारतीय परिषद में एक शोधकर्ता हूँ। और इस अद्भुत व्याख्यान के लिए धन्यवाद। मेरा मानना है कि लोग इसे लम्बे समय तक याद रखेंगे। मेरा सवाल परिषद में सदस्यता या प्रेक्षण से संबंधित है। तो, इस चीज का बुनियादी मानदंड क्या है कि एशिया के पांच देशों में से चार देश एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी हैं। और आपको मध्य एशियाई देशों में अपना क्या हित नज़र आता है, वे भी अति संवेदनशील हैं। और आपने ये सही बताया कि हिमालयी क्षेत्र और तियन शान की पहाड़ें तृतीय ध्रुव हैं; वहां पर सबसे अधिक संख्या में हिम नदियाँ हैं। तो, वो भी बहुत संवेदनशील है। तो, क्या उन्होंने आर्कटिक परिषद में कोई रूचि दिखाई है? धन्यवाद।

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

हाँ, हाँ, हाँ, महोदय।

अज्ञात वक्ता

आपके उत्कृष्ट व्याख्यान के लिए धन्यवाद। मेरे दो छोटे सवाल हैं। एक ये है कि आर्कटिक परिषद पर्माफ्रॉस्ट से निकलने वाले मीथेन की समस्या को कैसे संबोधित करने वाला है?

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

पर्माफ्रॉस्ट से मीथेन।

ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन: आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति

हाँ, ठीक है, हाँ।

अज्ञात वक्ता

और दूसरा सवाल है, आपने दिखाया कि क्या होने की संभावना है जैसे कि एशिया और कई अन्य देशों में समुद्र स्तर का बढ़ना और बाढ़ आना। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इसकी वजह से होने वाला आर्थिक नुकसान, ऊर्जा से होने वाले आर्थिक लाभ की तुलना में कम या ज्यादा हो सकता है?

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

ठीक है, आप आखरी सवाल पूछें।

संजीव कुमार: आईसीडब्ल्यूए

धन्यवाद महोदय। मैं डॉ. संजीव हूँ और मैं आईसीडब्ल्यूए का एक शोधकर्ता हूँ। महोदय आपका व्याख्यान बहुत ही अद्भुत था और इससे मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। मेरा सवाल चीन के बारे में है। आपने बहुत सही कहा कि वर्तमान प्रकरण में, जहाँ तक चीनी कार्यवाही का सवाल है उसमें कोई सैन्य बोध नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर दो साल पहले चीन द्वारा आर्कटिक पर जारी किए गए वाइट पेपर का सन्दर्भ देना चाहूँगा। और इसमें चीन ने बहुत ही स्पष्ट और प्रत्यक्ष बताया है कि आर्कटिक सहयोग को कैसे आगे बढ़ाना है। और इसमें बताया गया है कि यह बेल्ट और रोड पहल के माध्यम से बागे बढ़ाया जाना चाहिए। बेल्ट और

रोड पहल, ये एक विवादस्पद परियोजना है जैसा कि हम सभी जानते हैं। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण ये है कि, इसमें कहा गया है कि हमें मानव जाति के लिए आम गंतव्य वाला एक समुदाय बनाना है। उन्होंने आर्कटिक नीति को सीधे-सीधे मानव जाति के लिए आम गंतव्य वाला समुदाय बनाने से जोड़ा है, यह चीन द्वारा प्रस्तावित एक अत्यंत विवादस्पद भूराजनीतिक अवधारणा है। और आपने इस क्षेत्र में भूराजनीतिक रूपांतरण के बारे में बहुत ही सही कहा है। तो इस दस्तावेज के माध्यम से, वो भूराजनीतिक रूपांतरण लाना चाहते हैं, क्या आप इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे, धन्यवाद।

और मेरा दूसरा सवाल भी है। एक रिपोर्ट आई थी – आपने आर्कटिक में कॉस्को शिपिंग कारपोरेशन की संलग्नता के बारे में कहा था। इस चीनी कंपनी ने सूचना दी है कि अमेरिका ईरान से कच्चा तेल लाने से कॉस्को पर प्रतिबन्ध लगा रहा है, क्या इससे रूसी आर्कटिक में उनके कार्यों पर कोई प्रभाव पड़ा है? धन्यवाद।

ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन: आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति

माफ़ कीजिए, क्या आप दूसरा सवाल थोड़ा और विस्तार में समझाएंगे।

संजीव कुमार: आईसीडब्ल्यूए

पिछले साल…

टीसीए राघवन: विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक

कॉस्को पर अमेरिकी प्रतिबन्ध, भारतीय तेल परिवहन करने के कारण, क्या इससे प्रभाव पड़ेगा?

ओलाफुर रगनार ग्रिम्सन: आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति

ठीक है, खैर, मुझे एक बार फिर दोहराना चाहिए, मैंने कई देशों में आर्कटिक पर व्याख्यान दिया है। मुझसे बहुत मुश्किल से ही इस तरह के गहरी पहुँच वाले सवाल पूछे जाते हैं जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है। तो, मैंने पहले जो कहा उस पर एक और बयान देना चाहता हूँ, किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो चाहता हो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के मामलों में उसे गंभीरता से लिया जाए, के लिए अंतिम चुनौती यह है कि वह भारत आए और व्याख्यान दे, और फिर देखे कि क्या होता है।
तो मेरा मानना है कि ये सारे सवाल बहस और हम कैसे आगे बढ़ते हैं, इनके अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं संक्षेप में इन सभी का जवाब देने की कोशिश करूँगा।

सबसे पहले, मैं जो चीज आप सभी को बताना भूल गया था वह ये है कि आर्कटिक में पर्यावरण और आर्थिक प्रगति के बीच inaudible 101:41] है, ये नहीं भूलना चाहिए कि आर्कटिक में लगभग चार मिलियन लोग रहते हैं और वे वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो भी अन्य लोगों की तरह समृद्धि, जीविका और स्वास्थ्य सेवा, और अंतरसंपर्कता चाहते हैं।

और आर्कटिक के कई हिस्सों में ऐसी आर्थिक गतिविधियां होना पूरी तरह से यथोचित है, जो पर्यावरण के प्रति बिलकुल खतरा नहीं हैं। मुझे यकीन है कि यदि आप उत्तरी नॉर्वे जाते हैं, और आप मेयर, व्यवसाय अग्रणियों, वैज्ञानिकों या पर्यावरणविदों से बात करते हैं तो वे इस बात को गलत ठहराएंगे कि उत्तरी नॉर्वे की आर्थिक प्रगति से पर्यावरण को खतरा है। बल्कि इसके विपरीत, वो ये दावा करने की कोशिश करेंगे कि उत्तरी नॉर्वे एक अच्छा उदाहरण है कि आप पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाके कैसे रह सकते हैं और साथ ही उत्तरी नॉर्वे को सबसे अधिक समृद्ध नॉर्डिक क्षेत्र बताएंगे।

इसी तरह, ग्रीनलैंड में भी एक देश है जो आकार में पश्चिमी यूरोप का आधा है और जहाँ 55,000 लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड के आर्थिक विकास की परिकल्पना करना बहुत कठिन है जो बुनियादी रूप से ग्रीनलैंड के पर्यावरण के प्रति खतरा हो। मेरा मानना है, वास्तव में, भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप में ऊर्जा अर्थव्यवस्था का जो कुछ भी हो रहा है, वह अब तक

ग्रीनलैंड में हुई आर्थिक गतिविधि की तुलना में ग्रीनलैंड के पर्यावरण के प्रति एक अधिक बड़ा खतरा है। लेकिन उन्होंने बहुत ही सावधानी बरती है। उदाहरण के लिए, हमारा Alcoa लम्बे समय से ग्रीनलैंड में एक प्रगालक बनवाना चाहता था। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वह प्रगालक ग्रीनलैंड के सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संरचना में परिवर्तन का एक बुनियादी कारक बनेगा। इसलिए उन्होंने इसे इनकार कर दिया। एक कारण कि ग्रीनलैंड संभवतः हाइड्रो पॉवर स्टेशन बनाने और अपने पड़ोसी देशों को केबल के ज़रिए माल निर्यात करने में क्यों दिलचस्पी रखता है, क्योंकि इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।

बेशक, रूस, और कनाडा और अलास्का में, यह उठाए जाने वाला अधिक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि इन तीन देशों में होने वाली खनन गतिविधि भी निश्चित रूप से न केवल इन तीनों देशों के पर्यावरण बल्कि सम्पूर्ण ग्रह के पर्यावरण के भविष्य के प्रति कुछ हद तक खतरा है या खतरे का एक तत्व है। तो आर्कटिक में हमें दोनों तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि समुदाय कैसे दोनों तरह से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं और कैसे एक जिम्मेदार तरीके से पर्यावरण को सतत बनाए रखने में सक्षम हैं। और हमारे पास एक उदाहरण है, जहाँ की कहानी सोचनीय ढंग से अलग है, लेकिन मेरे विचार में पिछले पांच या छह सालों में, आर्कटिक विकास में पर्यावरणीय आयाम के बारे में जागरूकता को लगभग हर किसी ने पहचाना है।

आपने आर्कटिक विरोधाभास के बारे में सवाल पूछा, इन अर्थों में कि आर्कटिक के बर्फ का वास्तव में क्या हो रहा है, और फिर तेल की उपयोगिता इत्यादि का सवाल पूछा है। और बेशक ही यह एक दिलचस्प सवाल है। यही एक कारण है कि क्यों TOTAL-फ्रांसीसी और एलएनजी तेल कंपनी ने कहा कि वो आर्कटिक में ड्रिलिंग के काम में शामिल नहीं होंगे। यही एक कारण है कि क्यों कुछ उचित शिपिंग कम्पनियां ये कह रही हैं कि हम उत्तरी समुद्री मार्ग का उपयोग नहीं करेंगे। तो कंपनियों ने यह स्पष्ट रूप से पहचाना है कि आर्कटिक में तेल की खोज जारी रखना क्यों समस्याजनक है। लेकिन एक कारण कि क्यों रूस और चीन, मेरे विचार में उचित रूप से, दावा करते हैं कि साइबेरिया से लेकर नीचे शंघाई तक नई पाइपलाइन बिछाना सही है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? कोयले के बदले प्राकृतिक गैस।

तो कम से कम कुछ दशकों के लिए, मेरे विचार में रूसी आर्कटिक से प्राकृतिक गैस का उत्पादन और दोहन बढ़ाके इस मामले को सही नहीं ठहराया जा सकता है और यदि आप कोयला पॉवर स्टेशन और अन्य और भी मलिन ईंधन को बंद कर शुरू करते हैं, तो इससे सकारात्मक योगदान हो सकता है, हालांकि यह एक परिपूर्ण समाधान नहीं है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आर्कटिक विशाल नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का एक भंडार है। ग्रीनलैंड शायद पश्चिमी दुनिया में जल ऊर्जा का शेष रह गया आखरी – सबसे बड़ा जलाशय है। समुद्री केबल की नई प्रौद्योगिकी की सहायता से हम इसे यूरोप के माध्यम से अमेरिका में पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्वे देश नीदरलैंड, जर्मनी, ब्रिटन देशों में जल ऊर्जा निर्यात करने के लिए पहले ही केबल बनाने का काम शुरू कर चुका है ताकि उनकी ऊर्जा प्रणाली के चरम मांगों से निपटने में उन्हें सक्षम बनाया जा सके। और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डेटा स्टोरेज सेंटर डेनमार्क में क्यों बनवाने का निर्णय लिया, क्योंकि डेनमार्क से पवन ऊर्जा और नॉर्वे से जल ऊर्जा को संयुक्त रूप से केबल के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट तक पहुँचाया जा सकता है जिससे माइक्रोसॉफ्ट यूरोप का सबसे बड़ा डेटा सेंटर पूरी तरह से 100% स्वच्छ ऊर्जा पर संचालित करने में सक्षम होगा।

और मेरे अपने देश सहित आर्कटिक में हवा का स्वरूप यह आंकलन प्रस्तुत करता है कि विंड पॉवर स्टेशन बनाना और उपयोग करना अधिक किफायती है। उन्हें बहुत ज्यादा ऊंचा बनाने की जरूरत नहीं, पर उनकी उत्पादकता बहुत बढ़िया होती है। इसलिए फरो आइलैंड अपने पवन ऊर्जा की सफलता के कारण बहुत ही जल्द 100% स्वच्छ ऊर्जा उपयोग करने वाला द्वीप समूह बन जाएगा। तो यह एक बहुत ही जटिल तस्वीर है और यह लोगों के मन में भ्रम पैदा करता है क्योंकि कभी-कभी ये बताया जाता है कि आर्कटिक ऊर्जा का सवाल आज मात्र तेल के बारे में है। इसलिए यह – है, यह बेहतर है, दिलचस्प है। इसलिए यमाल नेनेट्स से ऊर्जा निर्यात दिलचस्प है। इसलिए ये पाइपलाइन दिलचस्प है। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया प्रस्ताव दिलचस्प है। और ये भी दिलचस्प है कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, फरो आइलैंड यूरोप के लिए समुद्री केबलों के नेटवर्क के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा का पॉवर हाउस क्यों बन सकते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आर्कटिक भी नवीकरणीय ऊर्जा भविष्य और आगामी वर्षों में कोयले से प्राकृतिक गैस से नवीकरणीय ऊर्जा के जिम्मेदार रूपांतरण का एक बड़ा हिस्सा है।

आर्कटिक रूचि के अर्थों में भारत की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? खैर, सबसे पहले, मैं कहूँगा कि आर्कटिक परिषद के एक अपतटीय देश के रूप में अपने पद की जिम्मेदारियों को यथोचित रूप से पूरा करना। इसका अर्थ है कि आर्कटिक नीति निर्माण में एक नए स्तर की प्राथमिकता देना, न केवल विज्ञान के अर्थों में बल्कि राजनय, ऊर्जा, आर्थिक गतिविधि और अन्य के अर्थों

में भी। टेबल में आपको एक सीट पहले ही मिल चुका है, मैं जानता हूँ कि यह एक सीमित सीट है लेकिन यह ऐसा सीट है जो आप फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान, कोरिया और अन्य देशों के साथ साझा करते हैं। चूंकि आपको स्वीकार किया गया है, इसलिए प्रेक्षक राज्यों की भूमिका और भी बढ़ गई है। लेकिन बेशक, चूंकि भारत को रूस से ऊर्जा का प्रस्ताव मिला है, तो अब ये सवाल यह उठता है कि क्या भारत आर्कटिक के ऊर्जा भविष्य का हिस्सा बनना चाहता है? आपके प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछा जा चुका है। और इस सवाल का जवाब देने में सक्षम होने के लिए आप यूरोप का मामला और चीन का मामला देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि तीसरी प्राथमिकता यह देखना होगा कि एशिया के अन्य देश इस बारे में क्या कर रहे हैं। आर्कटिक के संबंध में अन्य एशियाई देशों के समक्ष, न केवल समग्र भारत की बल्कि एशिया की भूमिका की क्या होनी चाहिए क्योंकि वास्तव में चीन, जापान और कोरिया जो कर रहे हैं वो हमारी अपेक्षा में अधिक बड़ा है, अधिक व्यापक है, अधिक सक्रिय है।

और जैसा कि किसी ने उल्लेख किया है, नई चीन आर्कटिक नीति इसका अच्छा प्रमाण है। यह शायद सबसे परिष्कृत आर्कटिक नीति है जो किसी भी देश द्वारा हाल के वर्षों में सामने रखी गई है। मैं मानता हूँ कि, पता नहीं यदि भारत के पास भी ऐसा दस्तावेज़ हैं, लेकिन आपके बौद्धिक ज्ञान पर आधारित परम्परागत विदेशी नीति-निर्माण को देखते हुए भारत के लिए उस प्रथा से गुज़रना एक दिलचस्प अनुभव हो सकता है। लेकिन फिर आपको अपने संसाधनों और आर्कटिक में अपनी आर्थिक उपस्थिति पर भी विचार करना होगा। एक मलेशियाई राजनयिक - व्यवसायी हैं जिनका नाम विंसेंट टैन है, जिन्होंने पिछले साल आइसलैंड का सबसे बड़ा होटल चेन खरीदा है। उन्होंने अब ग्रीनलैंड की राजधानी में एक नई होटल बनाने की योजना बनाई है। वे पूरे आर्कटिक में होटल चेन बनाना चाहते हैं क्योंकि वे आर्कटिक में बढ़ते एशियाई पर्यटन के लाभ में हिस्सा पाना चाहते हैं।

मैंने पहले भी न केवल ग्रीनलैंड में बल्कि अन्य भागों में भी खनन गतिविधि का उल्लेख किया है, और आपकी बड़ी कंपनियों को एक सामरिक निर्णय करना होगा कि आप 21 वीं सदी में दुर्लभ धातु या खनिज कहाँ से प्राप्त करेंगे? क्या आप पूरी तरह से आर्कटिक के बाहर से प्राप्त करेंगे या आर्कटिक के कुछ प्रदेश आपकी संसाधन योजना का हिस्सा बनेंगे? और यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है। यही एक कारण है कि ग्रीनलैंड में सोने का खनन शायद बहुत समृद्धकारी होगा, क्योंकि दुनिया की सभी बड़ी आईटी कंपनियों को अपने उत्पादन के लिए सोने की आवश्यकता होती है। और इन संसाधनों के प्रदाता के रूप में अस्थिर अफ्रीकी देशों से सौदा करके वे थक चुके हैं। और फिर बेशक, वैश्विक शिपिंग के विकास का मुद्दा है। बेशक, उस संबंध में भौगोलिक रूप से, भारत की अवस्थिति चीन, कोरिया और जापान से अलग है। मैंने कुछ सालों पहले आर्कटिक सर्कल की एक सभा में भारत के एक प्रतिनिधि का व्याख्यान सुना था, जिसमें उन्होंने भारत से एशिया और वहां से अरब की खाड़ी के ज़रिए ईरान में माल निर्यात करने के लिए समुद्री मार्गों की योजना बनाने की एक बहुत ही दिलचस्प धारणा प्रस्तुत की थी। और फिर माल को ईरान, यूरोप, रूस और फिर अटलांटिक से लेकर अमेरिका तक ट्रेनों में पहुँचाने की बात कही थी। यह योजना एक आकर्षक परिकल्पना थी। उस योजना में एकमात्र समस्या ईरान की राजनीतिक अवस्थिति है। लेकिन मैंने इसका उल्लेख इस बात के प्रमाण के रूप में किया है कि अब प्रमुख देश नई परिवहन मार्गों की तलाश कर रहे हैं। और बेल्ट और रोड या तथाकथित पोलर सिल्क रोड के बारे में आप जो कुछ भी सोचते हैं।

यदि आप चीन के एक नेता हैं, और इस बात की संभावना है कि आप 21 वीं सदी में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो आपको अत्यधिक आधुनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होगी। आपको आधुनिक रेलवे, आधुनिक बंदरगाहों, आधुनिक आईटी संचार की भी आवश्यकता होगी। ठीक उसी तरह जैसे पिछले समय में ब्रिटिश और अमेरिकी और फ्रांसीसी को अपने आर्थिक विकास के लिए सुएज़ कैनाल और पनामा कैनाल की आवश्यकता थी। यह बिल्कुल समझा जा सकता है कि चीन जैसा प्रमुख व्यापारिक देश परिवहन के लिए आधुनिक अवसंरचनाएं, आईटी संचार, रेलवे चाहता है, चाहे वो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनें हों या अन्यथा हों। हमारे पास अब ऐसी ट्रेनें हैं जो चीन से नीदरलैंड, यूरोप के आखरी सिरे तक माल पहुंचातीं हैं।
और मेरे ख्याल से ये एक सप्ताह में दो फेरे के साथ शुरू हुईं। अब ये सप्ताह में 25 बार फेरे लगाती हैं जो दर्शाता है कि सामानों के परिवहन का स्तर कितना बढ़ा है। तो भारत को भी एक तरह से या किसी अन्य तरह से इस सवाल का जवाब देना होगा कि आप 21 वीं सदी में यूरोप, एशिया, दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ अपनी आर्थिक क्रिया के लिए किस तरह के आधुनिक अवसंरचनाओं का उपयोग करने वाले हैं।

और चाहे हम बेल्ट और रोड की राजनीतिक रणनीतिक प्रकृति के बारे में कुछ भी कहें, एक ओर यह एक समझने-योग्य प्रस्ताव है। कठिनाई यह है कि यह अभी भी इतना अस्पष्ट है कि वास्तव में यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि इसका क्या अर्थ है। इसलिए जब उन्होंने नीतिगत दस्तावेज में पोलर सिल्क रोड की इस धारणा को शामिल किया, जिसके बारे में आपने उल्लेख किया था, चीन की आर्कटिक नीति, जिसके बारे में आप सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह आर्कटिक के बारे में उनकी परिष्कृत सोच का एक आकर्षक प्रमाण है।

हम सभी ने सवाल किया कि पोलर सिल्क रोड को सामान्य बेल्ट और रोड धारणा में शामिल करने का क्या अर्थ है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार इसे लॉन्च किया था, तब यह मौजूद नहीं था। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि चाहे चीन, रूस या आपके कोई पड़ोसी हो, वो सभी अब एशिया और यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों के बीच एक नया संचार अवसंरचना विनियोजित करने की प्रक्रिया में हैं, और भारत को अपना मन बनाना होगा आप इसका हिस्सा कैसे बनेंगे।

आर्कटिक परिषद की भूमिका निश्चित रूप से विकसित हुई है, लेकिन यह अभी भी वैज्ञानिक पर्यावरण मुद्दों के अर्थों में सीमित है। सैन्य मुद्दे मेज पर नहीं हैं। राजनीतिक मुद्दे मेज पर नहीं हैं। मंत्रिस्तरीय बैठक में आर्कटिक मंत्रियों, विदेश मंत्रियों ने भू-राजनीतिक भाषण को छोड़कर अन्य मुद्दों पर मजबूरन भाषण दिया था।

तो इसीलिए आर्कटिक सर्कल ने महत्वपूर्ण कार्य को पूरा किया है। क्योंकि हम इन सभी पहलुओं के बारे में बात कर सकते हैं, चाहे वो रणनीति, आर्थिक, पर्यावरणीय, भू राजनीतिक या कोई और पहलू हो। और इसलिए भी क्योंकि हमने आर्कटिक सर्कल की सभा में देश सत्र नामक सत्रों का भी आयोजन किया है। इसका अर्थ है कि फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड और अन्य देश आर्कटिक सर्कल की सभा में आए हैं और अपना मामला, अपनी नीतियां, अपनी परियोजना, अपनी योजनाएं पेश कीं हैं, और फिर प्रतिभागियों द्वारा उस पर पूछे गए सवालों को भी स्वीकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का एक व्यावसायिक प्रेक्षक होने के नाते मुझे यह उल्लेखनीय लगता है कि चीन, कोरिया, रूस, अमेरिका और अन्य देशों ने औपचारिक रूप से आर्कटिक सर्कल की सभाओ में संबोधन देने का विकल्प चुना है और फिर दर्शकों के सवालों का जवाब भी दिया है।

और इस तरह, हम इस विकास में कार्यात्मक उत्तरदायित्व निभा सकते हैं, क्योंकि वे सभी अब जानते हैं कि हर साल अक्टूबर में आर्कटिक मामलों के सबसे अधिक सक्रिय निर्वाचक क्षेत्रों से 2,000 से अधिक दर्शकों का विशाल जमघट उनकी परीक्षा लेगा।

और भारत को भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। सक्रिय आर्कटिक समुदाय के मध्य अपनी ये प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कि आप, यदि कहूँ तो, एक खिलाड़ी हैं। आपके पास बस ऐसे प्रेक्षकों के मध्य अध्यक्षता नहीं है जो आर्कटिक परिषद नहीं हैं। आप वृहद अर्थों में दुनिया के एक खिलाड़ी हैं। यही कारण है कि, यह दिलचस्प था कि कोरिया क्यों सालों पहले आर्कटिक सर्कल के सचिवालय आकर हमसे कहा कि हम आखरी रात को एक पार्टी देना चाहते हैं और हम हर किसी को इस पार्टी में आमंत्रित करना चाहते हैं। उस समय हमने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन उनके लिए यह एक दिलचस्प तरीके था ये संकेत देने का कि हम भी आपके परिवार का हिस्सा हैं। हम आपके साथ गाना और नाचना चाहते हैं और फिर आपको पार्टी में आमंत्रित करना चाहते हैं। और फिर, जापान आया और बोला, हम भी अगले साल एक पार्टी देना चाहते हैं, और इसी तरह चीन भी आया और ऐसा ही चलता रहा।

तो शायद भारत भी इसी तरह की एक पार्टी देने पर काम कर सकता है। अर्थात औपचारिक रूप से प्रस्ताव दे सकता है, मैं कोई मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। यदि भारतीय विदेश मंत्रालय और अन्य राजदूत, मान लें कि, भारत में एक शानदान रात आयोजित करना चाहते हैं। भोजन और भारतीय संगीत प्रस्तुत करना चाहते हैं जिस पर थिरका जा सकता हो। तो यह

औपचारिक प्रस्ताव देने का एक बहुत ही परिष्कृत तरीका होगा, और तब विदेश मंत्री को कहने की जरूरत नहीं होगी कि अरे दोस्तों हम भी यहाँ हैं। तो मेरे लिए इस पर गंभीर विचार कीजिए। आप इस वर्ष या अगले वर्ष आर्कटिक सर्कल में एक पार्टी आयोजित कर सकते हैं।

तो इसमें आर्कटिक संलग्नता का हिस्सा – ये अन्य मंच हैं। और आर्कटिक सर्कल ही एक मात्र मंच नहीं है। यह एक सबसे बड़ा, सबसे अधिक गतिशील मंच है, लेकिन ऐसे ही कई अन्य मंच भी हैं। तो ये समझना आवश्यक है। यह अंतर-शासकीय गतिविधियों का एक क्षेत्र मात्र नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक प्रतिभागी बनने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति एक प्रतिभागी बन सकता है।

पर्माफ्रॉस्ट के संबंध में, यह एक बहुत अच्छा मुद्दा है। वैज्ञानिक दृष्टि से, यह इस सहयोग में शायद उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है। हमने अक्सर आर्कटिक सर्कल सचिवालय में इस पर चर्चा की है कि हम कैसे पर्मफ्रोस्ट पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संवाद को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के इन सभी वर्णक्रमों में भविष्य की योजना पर जिन पहलुओं का प्रभाव पड़ेगा, यह उनमें से एक उपेक्षित पहलू है। तो आपका कहना बिलकुल सही है।

अमेरिकी प्रतिबंधों का इन सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खैर, दिलचस्प बात यह है कि यदि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का नेता होता, तो मैं इस बारे में चिंता करता। पूरी दुनिया, यहां तक कि यूरोप, पश्चिमी यूरोप आपकी बातों को नहीं सुन रहा है। जब चीन ने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना करने का निर्णय लिया, ओबामा ने इसका कड़ा विरोध किया था। मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया उन अन्य देशों में से एक है जिसे लिस्ट किया गया था, भारत के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे पता नहीं (बहु वक्ता)

हाँ, हाँ, बिलकुल। बिलकुल, हाँ। और मेरे अपने देश, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अन्य देश। तो अब, कोई भूमिका नहीं है। ट्रम्प भी यहीं बात कह रहे हैं, कि बेल्ट और रोड का हिस्सा मत बनो। ये याद रखा जाना चाहिए कि ट्रम्प वह पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कहा था कि हमें चीन के साथ काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे पहले ओबामा ने भी यही बात कही थी। युद्ध नज़र आने पर आपमें से अधिकतर लोगों ने अपना कन्धा झुका लिया। फिर ट्रम्प आए और उन्होंने कहा कि बेल्ट और रोड के साथ काम मत करो। इस मामले का तथ्य ये है कि नाटो के चार या पांच या छह देश पहले से ही औपचारिक रूप से बेल्ट और रोड में भागीदार हैं।

यहां तक कि लक्समबर्ग, जो मेरा पसंदीदा उदाहरण है, पिछले साल बेल्ट और रोड के साथ औपचारिक रूप से जुड़ा है। लक्समबर्ग नाटो का संस्थापक सदस्य है। यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है। यूरोपीय संघ के वित्तीय संरचना का एक प्रमुख देश है। मुझे नहीं लगता कि फ्रांस या जर्मनी या यहां तक कि अमेरिका ने उन्हें बेल्ट और रोड का हिस्सा बनने से रोकने के लिए कोई बड़ा प्रयास किया था। इटली, निश्चित रूप से बेल्ट और रोड का सदस्य है। आर्कटिक सर्कल में नॉर्वे के प्रतिनिधि ने भी शंघाई में कहा, नॉर्वे, हम शायद औपचारिक रूप से बेल्ट और रोड के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत परियोजना की अनुवीक्षा करेंगे। लेकिन बेल्ट और रोड में केवल व्यक्तिगत परियोजनाएं ही शामिल हैं। तो ये सब बस यही कहने का एक तरीका था कि नॉर्वे भी इसका हिस्सा बनेगा।

तो, मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस पर अमेरिका, माननीय ओबामा और ट्रम्प दोनों के निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब उपराष्ट्रपति पेंस पिछले साल आइसलैंड आए थे, उन्होंने दो संदेश दिए थे और ये सच है, उन्होंने बस दो सन्देश दिए थे। एक सन्देश में उन्होंने आर्कटिक में हमें चीन के खिलाफ चेतावनी दी थी। और दूसरा में उन्होंने हमें OHI जो एक 5G दूर संचार कंपनी है, उसके खिलाफ चेतावनी दी थी। इसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया निम्नुसार थी, ऐसे दो देश हैं जो आर्कटिक पर चीन के साथ मिलकर सक्रिय और औपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और वो देश हैं कोरिया और जापान। उन्होंने उनसे एशिया में आपके मुख्य सहयोगी बनने को कहा था। क्या आपने उन्हें ये बताया है? बेशक, नहीं बताया है। और दूर संचार कंपनी और 5G पर मैंने प्रतिक्रिया देते हुए इंगित किया कि आइसलैंड की एक दूर संचार कंपनी जो 5G पर OHI के साथ सक्रियता से काम कर रही है, वह वास्तव में एक अमेरिकी निवेश फर्म की कंपनी है। तो मैंने कहा, आपको यहाँ इतनी दूर आइसलैंड में

आने की बजाय इस बारे में अपने देश की कंपनियों के मालिकों से बात करनी चाहिए थी। वर्तमान, हम उस कंपनी के मालिक नहीं हैं। वो कंपनी आप लोगों की है, अलास्का के पीटी कैपिटल की है।

तो अब हम राजनयिक समुदाय में बहुत चहल-पहल की अपेक्षा करते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। और मेरा मानना है कि अमेरिका को बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है, यह तय करने के लिए कि इसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भले ही रूस और चीन ऊर्जा और बाकि के अन्य मुद्दों पर साथ-मिलकर काम कर रहे हों पर इसकी कोई दीर्घावधिक गारंटी नहीं है कि वो आगे भी भागीदार बने रहेंगे।

एक प्रसिद्ध कहानी है कि जब हो ची मिन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोसीजिन वियतनाम गए थे तब वो वापस आने से पहले झोउ एनलाई के साथ मुलाकात करने के लिए रुक गए थे। और बेशक, कोसीजिन ने बहुत ही विनम्र राजनयिक तरीके से रूस और चीन के बीच ठोस साझेदारी की बात कही थी। यदि आप विश्लेषण करें तो हाँ, यह तय करने में कम से कम 1,000 साल लगेंगे कि ये एक ठोस साझेदारी है या नहीं। कोसीजिन को बेशक यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, इतना लम्बा समय नहीं लगेगा। यदि आप विश्लेषण करें तो हाँ शायद इसमें 900 साल लग सकते हैं। तो हमें इस बात से अवगत रहना चाहिए कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हम आज जो तस्वीर देख रहे हैं वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि मानव इतिहास में पहली बार हम एक ओर आर्कटिक के नए भू-राजनीतिक महत्व और दूसरी ओर हिमालय-तृतीय ध्रुव के भू-राजनीतिक महत्व के गवाह बन रहे हैं। और उस सहयोग को सफल बनाने के लिए इस जुड़ाव की रूपरेखा और नियमों का गठन करने की जिम्मेदारी हम सभी पर है।

टीसीए राघवन

धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महामहिम। आपके शानदार व्याख्यान और धैर्य के साथ सभी सवालों का जवाब देने, दोनों के लिए धन्यवाद। हम इसे जारी रख सकते हैं लेकिन अभी पूरा दिन आर्कटिक पर चर्चा होना बाकी है और उसके बाद संगोष्ठी होगी और मैं आशा करता हूँ कि महामहिम आप संगोष्ठी में उपस्थित होंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद सभी लोग आपके साथ आगे भी जुड़ना चाहेंगे।

*****